विचार बिन्दु

त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जायें और सूखी रोटी खायी जाये, त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाये। –सुफियान सौरी

सालाना एक करोड़ रोजगार के अवसर विकसित करने की दरकार

गौल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट चुनौतीपूर्ण होने के साथ ही आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरुरी भी हो जाती है। रिपोर्ट में जीवीए यानी कि ग्रास वेल्यू एडिशन 6.5 प्रतिशत बनाए रखने के लिए 2025 से 2030 के दौरान सालाना एक करोड़ रोजगार के अवसर विकसित करना आवश्यक है। हांलाकि जिस तरह से देश की इकोनोमी उछालें भर रही है उस स्थिति में इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल भी नहीं लगता है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनोमी बनने के लिए हमें रोजगार के नित नए अवसर तो विकसित करने ही होंगे वहीं इस तरह की आर्थिक नीति तय करनी होगी जिससे देश में स्थानीय स्तर पर आय के साधन विकसित हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़े, मेट्रोपोलिटन सिटीज के स्थान पर छोटे शहरों कस्बों में आर्थिक गतिविधियां बढ़े। इसके लिए सरकार को रोडमैप बनाकर आगे बढ़ना होगा हांलाकि जिस दिशा में देश की आर्थिक नीति ले जा रही है उसमें मामूली सा बदलाव ही करना होगा। विकास के केन्द्र को विकेन्द्रित करना होगा। बड़े शहरों की और पलायन को रोकते हुए नए आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र विकसित करना होगा।

यह बात साफ हो जानी चाहिए कि एमएसएमई-मैन्यूफेक्चरिंग-विनिर्माण क्षेत्र ऐसा है जहां रोजगार के अवसर अधिक विकसित होते हैं। देश में एक करोड़ सालाना रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए पहले से ही कार्ययोजना तैयार है केवल इस कार्ययोजना को नए सिरे से अंजाम देने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद चीन की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और उसके चलते दुनिया के देश भारत की और आशा की नजर से देख रहे हैं। यही कारण है कि एक और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की और रुख कर रही है तो दूसरी और जिस तरह से देश में आधारभूत ढांचें का विकास हो रहा है उससे आर्थिक विकास को गति मिली है। अटल बिहारी वाजपेई सरकार के समय स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनी और जिस तरह से मोदी सरकार में गड़करी के नेतृत्व में हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे आदि बनकर तैयार हो रहे हैं उससे आवागमन आसान हआ है। इससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है।

एक सकारात्मकता यह भी है कि देश में आज युवा पीढ़ी का वर्चस्व है और ऐसे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और बढ़ना दोनों ही सहज हो जाता है। सरकार को इस तरह की नीतियां बनानी होगी ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकेन्द्रीत विस्तार हो और रोजगार परक गतिविधियां आसान हो, बाजार के हालात अच्छे होने के साथ ही निर्यात को और अधिक आसान बनाया जाए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां रोजगार के 80 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। अब सरकार को रियल स्टेट को मेट्रोपोलिटन शहरों से छोटे शहरों-कस्बों की और शिफ्ट करने पर ध्यान देना होगा जिससे बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। इसी तरह से बैंगलोर को आईटी का केन्द्र बनाने या गुरुग्राम या नोएडा या गेटर नोयेडा या अन्य इसी तरह के देश के विभिन्न हिस्सों में केन्द्र विकसित होने से इन स्थानों पर अत्यधिक दबाव बड़ा है और उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। ऐसें में टियर 2 व टियर 3 के शहर कस्बों में आईटी हब विकसित करने, इनके आसपास के क्षेत्रों में छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, इन स्थानों पर जीसीसी यानी कि ग्लोबल केपेसिटी सेंटर विकसित करने के आवश्यकता है। लघु उद्योगों के विकास और उनके निर्यात को बढाना होगा। मोदी सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और छोटे उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक्ड योजना के तहत प्रोत्साहन से निश्चित रुप से औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। आज भी कपड़ा, जूते, खिलौने, खाद्य सामग्री और इसी तरह के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार ध्यान भी दे रही है तो दूसरी और विकास और रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं।

वैसे देखा जाए तो पिछले बीस सालों में 19 करोड़ 60 लाख नए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। इसमें भी गत एक दशक में अधिक तेजी आई हैं। कोरोना के बाद से परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया है तो वैश्विक सिनेरियों भी भारत के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया के देश खास तौर से रूस-यूक्रेन, इजराइल-

हमास-ईरान आदि आपस में जूझ रहे हैं तो योरोपीय देश, अमेरिका आदि देश अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे है। ऐसे में भारत के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर सामने आ रहे हैं। फिर देश का राजनीतिक नेतृत्व भी जिस तरह से दुनिया के देशों पर डोमिनेट होकर के उभरा है उसके भी सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सख्त फैसले लेने वाली सरकार आज की आवश्यकता है और अमेरिका के हालिया चुनाव नतीजे इसे साफ करते हैं। एक सकारात्मकता यह भी है कि देश में आज युवा पीढ़ी का वर्चस्व है और ऐसे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और बढ़ना दोनों ही सहज हो जाता है। सरकार को इस तरह की नीतियां बनानी होगी ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकेन्द्रीत विस्तार हो और रोजगार परक गतिविधियां आसान हो, बाजार के हालात अच्छे होने के साथ ही निर्यात को और अधिक आसान बनाया जाए। ऐसे में विकास या आर्थिक गतिविधियां केन्द्रीकृत ना होकर के विकेन्द्रीत होगी और स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार के अवसर व कौशल विकास संभव हो पाएगा। आज के हालात में गौल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट इसलिए चिंतनीय नहीं होनी चाहिए कि देश में सालना एक करोड़ रोजगार के अवसर विकसित करना कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं होगा केवल सोच व क्रियान्वयन पर जोर देना होगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 21 नवम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2081, पुष्य नक्षत्र दिन 3:53 तक, शुक्ल योग दिन 12:01 तक, वणिज करण सायं 5:04 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग और गुरू पुष्य योग सूर्योदय से दिन 3:35 तक है। रवियोग दिन 3:35 से आरम्भ होगा। भद्रा सायं 5:04 से आरम्भ होगी। आज सायन धनु में सूर्य प्रवेश रात्रि 1:27 से करेगा। आज छीट छट, गुरू पुष्य योग है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:14 तक, चर 10:53 से 12:13 तक, लाभ-अमृत 12:13 से 2:51 तक, शुभ 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:55, सूर्यास्त 5:30

मेष
परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मकर
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अनावश्यक वाद-विवाद करना ठीक नहीं रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

साइबर अपराधों का बढ़ता कहर

बैंककर्मियों, सिम विक्रेताओं व ई-मित्र केंद्रों की मिलीभगत ने जनता को लूटा, पुलिस परेशान

सुनील दत्त गोयल

डिजिटल इंडिया के सपने के साथ देश तेजी से तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति की आड़ में साइबर अपराधों का खतरा भी गंभीर रूप से बढ़ गया है। बैंक कर्मियों, सिम कार्ड विक्रेताओं और ई-मित्र केंद्रों की मिलीभगत ने इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। मेहनतकश नागरिकों की कमाई पर साइबर अपराधियों का निशाना अब एक विकराल समस्या बन गई है। इस मिलीभगत से जनता का विश्वास टूट रहा है और अपराधियों को लूट-खसोट का खुला मैदान मिल रहा है।

बैंकों की कमजोर प्रणाली

बैंक, जो जनता के धन और विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं, अब खुद धोखाधड़ी के मामलों में सवालों के घेरे में हैं। कई बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खोल दिए जाते हैं। केवाईसी प्रक्रिया, जो सुरक्षा का मुख्य आधार है, अक्सर महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसके कारण अपराधी फर्जी खातों का उपयोग कर लेन-देन को अंजाम देते हैं।

इसके अलावा, संदिग्ध लेन-देन की अनदेखी बैंकिंग प्रणाली की सबसे बड़ी खामी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, 50,000 से अधिक की नकद जमा या निकासी होने पर तुरंत उस खाते की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, महीने में 1,00,000 से अधिक एवं 1 वर्ष में 10 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन आरबीआई के द्वारा अधिकृत है इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर खाताधारक से संपर्क किया जाना चाहिए और ट्रांजैक्शन की सत्यता की पुष्टि की जानी चाहिए। बैंक कर्मियों द्वारा मशीन किसी को जारी करने पर यह सुनिश्चित करना चाहिए की आवेदक के व्यापार के लिए सही में इसकी आवश्यकता है भी या नहीं। जहाँ भी मशीन जारी की जाती है वहां की वीडियो रिकॉर्ड की जानी चाहिए जिसमें बैंक कर्मी के साथ व्यापारी के साथ लाइव लोकेशन पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।

आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी असाधारण अमाउंट के खाते में जमा होने पर उसे तुरंत होल्ड पर रख दिया जाना चाहिए और खाताधारक से संपर्क करके यह मालूम करें कि यह पैसा उसके पास कहां से आया वह उसका स्त्रोत बताएं अन्यथा वह पूरी सूचना आयकर विभाग को तुरंत सूचित कर दें और पुलिस को सूचना कर दें क्योंकि एक सामान्य बचत खाते में इस तरह का बड़ा अमाउंट अगर आता है तो अपने आप ही शक के घेरे में आ जाता है और बैंक वालों के लिए यह मालूम करना बड़ा आसान काम है कि अमाउंट किसका आया और कहां से है यह दोनों उनको मालूम पड़ जाता है और यह अमाउंट अगर 3-4 दिन के लिए भी होल्ड कर दिया जाए तो जिसके साथ भी धोखाधड़ी हुई है उसकी सूचना पुलिस व बैंक तक पहुंच भी जाएगी और वह पैसा बैंक के खाते में ही जमा रह जाएगा।

सिम कार्ड विक्रेताओं का गैर-जिम्मेदार रवैया

टेलीकॉम सेक्टर में भी गहरी मिलीभगत देखने को मिल रही है। सिम कार्ड वितरकों द्वारा बिना उचित दस्तावेज़ सत्यापन के सिम जारी करना एक आम बात हो गई है। फर्जी पहचान पत्रों के सहारे जारी किए गए सिम कार्डों का इस्तेमाल अपराधी जनता को ठगने और गुमनाम रहने के लिए करते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर 10-15 सिम कार्ड तक जारी कर दिए जाते हैं, जबकि नियमानुसार अधिकतम 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों की इस मिलीभगतसे सिम कार्डों का दुरुपयोग बढ़ गया है।

ई-मित्र केंद्र: धोखाधड़ी का नया अड्डा

जहां एक ओर ई-मित्र केंद्रों को सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है, वहीं ये केंद्र अब साइबर अपराधों का नया अड्डा बनते जा रहे हैं। ई-मित्र केंद्रों पर ग्राहकों की जानकारी बिना उचित सत्यापन के दर्ज की जाती है, जिससे उनकी गोपनीय जानकारी अपराधियों तक पहुंच जाती है। कई ई-मित्र केंद्रों पर फर्जी खातों को खोलने और सिम कार्ड वितरित करने में मिलीभगत के आरोप भी लग चुके हैं। यह स्थिति न केवल जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि डिजिटल सेवाओं पर से भरोसा भी कम करती है। ई-मित्र केंद्रों पर काम कर रहे कर्मचारियों की भी पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा गहन जांच करने की आवश्यकता है यदि कोई कर्मचारी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे राष्ट्रदोह की श्रेणी का अपराध मानते हुए आजीवन इस तरह के कार्य करने के लिए बैन कर देना चाहिए।

संस्थानों की मिलीभगत से अपराधियों को बढ़ावा

बैंक कर्मियों, सिम विक्रेताओं और ई-मित्र की मिलीभगत ने साइबर अपराधियों को एक सुनहरा मौका दिया है। ये अपराधी जनता की मेहनत की कमाई को ठगकर उसे देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहे हैं। हाल के मामलों में देखा गया है कि कैसे फर्जी खातों और सिम कार्डों का उपयोग आतंकी फंडिंग और अन्य अपराधों में किया गया। क्या है समाधान?

इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को तुरंत कदम उठाने होंगे। बैंकों को अपनी केवाईसी प्रणाली को सख्त बनाना होगा। बड़े लेन-देन पर रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी होगी ताकि वे धोखाधड़ी के मामलों में शामिल न हों।

सिम कार्ड वितरण के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सख्त नियम लागू करने होंगे। फर्जी दस्तावेजों पर सिम जारी करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए।ई-मित्र केंद्रों की नियमित जांच और निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। इन केंद्रों द्वारा की गई किसी भी मिलीभगत पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और लाइसेंस रद्द करना चाहिए। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने देश में डिजिटल सुरक्षा की गंभीरता को उजागर किया है। बैंक कर्मियों, सिम विक्रेताओं और ई-मित्र केंद्रों के कर्मचारियों की मिलीभगत से ना केवल जनता की संपत्ति छीन रही है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। यदि समय रहते इन संस्थानों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो जनता का विश्वास और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। **धन्यवाद,**

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक
इम्पीरियल चैंबर ऑफ़
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जयपुर,
राजस्थान

बढ़ता वायु प्रदूषण: दिल्ली ही नहीं, देश के लिए भी चिंता

राम शर्मा

भारत की राजधानी दिल्ली ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में एक अविश्वसनीय प्रतिष्ठा अर्जित की है। गंभीर वायु प्रदूषण की बार बार होने वाली घटनाएं, विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई हैं। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है; इसका प्रभाव पूरे देश में है, जोकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता, पर्यावरणीय स्थिरता और भारत की अंतरराष्ट्रीय धारणा को प्रभावित करता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मूल में कई कारण हैं। ये कारण प्राकृतिक और मानवजनित दोनों का ही मिलाजुला रूप हैं। इनमें मुख्य कारक हैं- वाहनों से निकलने वाली धुआं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और फसलों के अवशेषों को जलाने से उठी धुआं।

दिल्ली की सड़कें 12 मिलियन से ज़्यादा वाहनों से भरी हुई हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उच्च स्तर के प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। दिल्ली और उसके आस-पास की फैक्ट्रियां और छोटे पैमाने के उद्योग हवा में काफ़ी मात्रा में ज़हरीली गैसें और कण छोड़ते हैं। अनियमित निर्माण गतिविधियां काफ़ी धूल पैदा करती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में किसान खेतों को साफ़ करने के लिए पराली जलाते हैं, जिससे अक्टूबर-नवंबर के दौरान पार्टिकुलेट प्रदूषण में सालाना बढ़ोतरी होती है। सर्दियों के दौरान, हवा की कम गति और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण प्रदूषक ज़मीन के पास फंस जाते हैं, जिससे धुंध और भी खराब हो जाती है। प्लास्टिक सहित कचरे को खुले में जलाने से जहरीले उत्सर्जन में योगदान होता है। ये कारक मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां वायु की गुणवत्ता नियमित रूप से 'खतरनाक' स्तर तक गिर जाती है, जिससे न केवल दिल्ली के निवासी बल्कि पूरा देश गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण से उत्पन्न दुष्प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से परे फैला हुआ है। दिल्ली के वायु प्रदूषण से समूचा एनसीआर रीजन का जनस्वास्थ्य खतरे में है। प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। यह हृदय संबंधी समस्याओं को भी बढ़ाता है और फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है।

वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के उपचार से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यह बोझ केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल गया है। क्योंकि दूसरे राज्यों से लोग काम या पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं और यहां की जहरीली हवा के संपर्क में आते हैं। उच्च प्रदूषण स्तरों के संपर्क में आने वाले बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसका असर देश के भावी कार्यबल पर पड़ सकता है। दिल्ली से प्रदूषक अक्सर पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।

खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर कम होता है, जिससे उद्योग और सेवाएं प्रभावित होती हैं। प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण कार्यदिवसों का नुकसान आर्थिक नुकसान में इज़ाफा करता है। स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण शमन उपायों पर सरकारी खर्च अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं से संसाधनों को हटा देता है। दिल्ली, एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते, प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में गिरावट से ग्रस्त है। इसका भारत में समग्र पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।

ओजोन जैसे प्रदूषक फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे दिल्ली से प्रदूषण के प्रसार से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उपज कम हो सकती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता को लेकर चिंताओं के कारण व्यवसाय और निवेशक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में परिचालन स्थापित करने से कतराते हैं।

दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। दिल्ली के उद्योगों और वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। वायुजनित प्रदूषक नदियों और झीलों पर जम जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, यमुना नदी प्रदूषक जमाव से ग्रस्त है, जिससे इसकी पहले से ही गंभीर स्थिति और भी खराब हो गई है।

सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जमाव के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा, प्रभावित क्षेत्रों में वनस्पति और वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाती है।हवा से भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों के कृषि भूमि पर जमाव से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लगातार धुंध और खराब वायु गुणवत्ता निवासियों में चिंता, अवसाद और तनाव पैदा कर सकती है। परिवार अक्सर इस दुविधा से जूझते हैं कि दिल्ली छोड़ दें या नहीं, जिससे सामाजिक स्थिरता बाधित होती है। गंभीर प्रदूषण के दौरान स्कूल अक्सर बंद रहते हैं, जिससे शिक्षा बाधित होती है और माता-पिता और बच्चों पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण शहरी पलायन बढ़ रहा है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में दिल्ली की स्थिति अक्सर अंतरराष्ट्रीय पोर्टों में प्रमुखता से दिखाई देती है, जो पर्यावरण प्रबंधन के साथ भारत के संघर्षों को उजागर करती है।

राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता भारत की वैश्विक जलवायु और प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता पर सवाल उठाती है। विदेश से पेशेवर और निवेशक दिल्ली में आने या निवेश करने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रदूषण स्तर के कारण भारत की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट को संबोधित करने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ संभावित समाधानों में शामिल हैं। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है।

उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानदंडों का सख्त प्रवर्तन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना आवश्यक है। किसानों को पराली निपटान के वैकल्पिक तरीकों, जैसे कि हैप्पी सीडर जैसी मशीनों का उपयोग करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, पराली जलाने पर अंकुश लगा सकता है।

दिल्ली और उसके आस-पास हरियाली बढ़ाना वायु प्रदूषण के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के व्यापक कार्यान्वयन से दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता सुधार हासिल करने में मदद मिल सकती है। नागरिकों को उनके विकल्पों के प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन के बजाय निजी वाहनों का उपयोग करना, व्यवहार में बदलाव ला सकता है।

दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट तत्काल और निरंतर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आ ान है। जबकि स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम दिल्ली में सबसे अधिक महसूस किए जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में फैलता है, जो आर्थिक उत्पादकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भारत की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करता है।

इस चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी नीति, तकनीकी नवाचार, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और नागरिक भागीदारी शामिल हो। दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर, भारत एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकता है जहाँ स्वच्छ हवा एक मौलिक अधिकार हो, जिससे स्वस्थ जीवन और अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

–राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाईजर भर्ती कैम्प 24 से

अजमेर, (कासं)। रोजगार कार्यालय एवं भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारी भर्ती कैंप 24 नवम्बर से जिले की पंचायत समिति स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

एसएससीआई आरटी नीमच के कमांडेन्ट महिपाल सिंह ने बताया कि आगामी 24 नवम्बर को पंचायत समिति केकड़ी, 25 नवम्बर को पंचायत समिति पीसांगन, 26 नवम्बर को पंचायत समिति सरवाड़, 27 नवम्बर को पंचायत समिति जवाजा, 28 नवम्बर को पंचायत समिति मसूदा, 29 नवम्बर को पंचायत समिति भिनाय, 2 दिसम्बर को पंचायत समिति अरांई, 3 व 5 दिसम्बर को पंचायत समिति श्रीनगर, 4 व 6 दिसम्बर को पंचायत समिति सिलोरा किशनगढ़ में भर्ती केम्प आयोजित होंगे। भर्ती केम्प का समय प्रात: 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जवान के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवा की उम्र 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

पीबीएम हॉस्पिटल में सौ वर्षीय वृद्ध का सफल नेत्र ऑपरेशन

भींयाराम ने सादगीपूर्ण जीवनशैली और नशामुक्त आदतों की बदौलत अपना स्वास्थ्य सही बनाये रखा

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सालय में चिकित्सा विज्ञान और सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जब वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. जे. मुरली मनोहर ने 100 वर्षीय भींयाराम गोदारा की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान लेंस प्रत्यारोपण किया गया और अब मरीज स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं।

नोखागांव (नोखा) निवासी चौधरी भींयाराम गोदारा का यह जीवन का पहला ऑपरेशन था। अपनी सादगीपूर्ण जीवनशैली और नशामुक्त आदतों की बदौलत उन्होंने सौ वर्ष की उम्र में भी अपना स्वास्थ्य बनाए रखा। चौधरी भींयाराम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक सक्रिय रहे। वे अपने गांव के सरपंच के रूप में लंबे समय तक सेवाएं देकर गांववासियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बने। डॉ. मुरली मनोहर, जो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, ने बताया कि इस उम्र में ऑपरेशन करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन चौधरी भींयाराम का सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास इस प्रक्रिया को सहज और सफल बनाने में सहायक रहा। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अब भींयाराम अपने नए दृष्टिकोण से जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके पोते और सामाजिक कार्यकर्ता मुरली गोदारा भी मौजूद रहे। मुरली गोदारा ने पीबीएम हॉस्पिटल की पूरी चिकित्सा टीम और विशेष रूप से डॉ. जे. मुरली मनोहर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुरली मनोहर और उनकी टीम ने जो से